



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 86]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2019/फाल्गुन 15, 1940

No. 86]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2019/ PHALGUNA 15, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 27 फरवरी, 2019

सं. टीएएमपी/46/2016—बीपीसीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/46/2016- बीपीसीएल

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश**(फरवरी, 2019 के 25 वें दिन पारित)**

मामला जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) में परिचालित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के वर्तमान दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. बीपीसीएल के वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अनुसार 8 फरवरी, 2017 के आदेश संख्या टीएएमपी/46/2016-बीपीसीएल के द्वारा अनुमोदित किये गए थे। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 06 मार्च 2016 के राजपत्र सं. 94 में अधिसूचित हुआ था। आदेश में प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च, 2019 तक वैध थी।

3.1. इस पृष्ठभूमि में बीपीसीएल ने 1 फरवरी 2019 के पत्र संख्या बीपीसीएल/जेएनपीटी/ओपीएस/टीएएमपी में बताया है कि वह 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होने वाली नई दरों का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। यह भी सूचित किया गया है कि उक्त प्रक्रिया में निविदा, डाटा एकत्र करना और वार्षिक राजस्व अपेक्षा की गणना के साथ-साथ नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना भी निहित है।

3.2. तदनुसार, बीपीसीएल ने दरमानों की वर्तमान वैधता को तीन महीने की अवधि के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक, बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि वे उपभोक्ताओं से उसे प्राप्त कर सकें। बीपीसीएल ने यह भी बताया है कि प्राधिकरण की अपेक्षानुसार नया प्रस्ताव पूरा हो जाने पर 30 जून 2019 तक या उससे पहले प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

4.1. चूंकि बीपीसीएल का वर्तमान प्रशुल्क 31 मार्च, 2019 को समाप्त हो जायेगा और बीपीसीएल द्वारा ऊपर बताये कारणों से किये गए अनुरोध के आधार पर और बीपीसीएल द्वारा दायर (किये जाने वाले) प्रस्ताव की प्रक्रिया में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए और प्रशुल्क में शून्यता से बचने के उद्देश्य से बीपीसीएल के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का 31 मार्च, 2019 से इतर विस्तार करना उपयुक्त पाया जाता है।

4.2. उक्त स्थिति को देखते हुए, यह प्राधिकरण बीपीसीएल के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का 3 महीने की अवधि के लिए यानी 1 अप्रैल, 2019 से 30 जून, 2019 तक विस्तार करने को प्रवृत्त है, जैसा बीपीसीएल ने अनुरोध किया है।

4.3. जहां तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का संबंध है, इस पर सुविचार करते हुए कि वैधता का विस्तार 30 जून 2019 तक किया गया है, और संशोधित दरमान समय पर लागू हो जाने चाहिए, बीपीसीएल को सलाह दी जाती है कि वह अपने प्रशुल्क के सामान्य संशोधन का प्रस्ताव 30 अप्रैल 2019 तक दाखिल कर देवे न कि 30 जून, 2019 तक, जैसा बीपीसीएल ने अनुरोध किया है।

4.4. यदि उनके निष्पादन की समीक्षा के दौरान 01 अप्रैल, 2019 के बाद की अवधि में ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल से अधिक अतिरिक्त अधिशेष पाया गया तो ऐसे अतिरिक्त अधिशेष का निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः सैट-ऑफ कर दिया जायेगा।

टी.एस.बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)**[विज्ञापन-III/4/असा./562/18]****TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION****Mumbai, 27 February, 2019**

No. TAMP/46/2016-BPCL.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited in the Jawaharlal Nehru Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/46/2016-BPCL****The Bharat Petroleum Corporation Limited**

- - -

Applicant

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25 day of February, 2019)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) operating the Liquid Cargo berth at the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of BPCL was approved by this Authority vide Order No. TAMP/46/2016-BPCL, dated 8 February 2017 following Tariff Guidelines of 2005. This Order was notified in the Gazette of India on 06 March 2017 vide Gazette No. 94. The Order prescribed a tariff validity till 31 March 2019.

3.1. In this backdrop, the BPCL vide its letter dated no. BPCL/JNP/OPS/TAMP dated 1 February 2019 has stated that it is in the process of formulating a proposal for new rates with effect from 01 April 2019. The said working is reported to include tendering, collecting data and working out the annual revenue requirement vis-à-vis return required on the capital employed.

3.2. Accordingly, the BPCL has requested to extend the validity of its existing Scale of Rates for a further period of three months i.e. upto 30 June 2019 to enable them to charge the same from the consumers. The BPCL has also stated that, the new proposal would be submitted by or before 30 June 2019 on completion as per TAMP requirement.

4.1. Since the validity of the existing tariff of BPCL will expire on 31 March 2019 and based on the request made by BPCL for the reasons cited by it and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the BPCL and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing tariff of BPCL beyond 31 March 2019.

4.2. In view of the above position, this Authority is inclined to extend the validity of the existing tariff of BPCL for a period of 3 months i.e. from 01 April 2019 to 30 June 2019, as requested by BPCL.

4.3. With regard to submission of the proposal, considering that the validity has been extended upto 30 June 2019 and the revised SOR may have to be in place in time, the BPCL is advised to file its proposal for general revision of its tariff by 30 April 2019, instead of 30 June 2019, as requested by BPCL.

4.4. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./562/18]